उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून

E-mail :infodirector.uk@gmail.com
Website :www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 06 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(09/177)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी में ''पांचवां देहरादून इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिवल'' का शुभारम्भ किया। उन्होंने फिल्म कलाकारों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड का सौन्दर्य फिल्मों की शूटिंग के लिये अनुकूल है, एक प्रकार से पूरा उत्तराखण्ड एक ओपन स्टूडियो है। देश के विभिन्न भागों से फिल्म निर्माता उत्तराखण्ड के प्रति आकर्षित हुए। मलयाली फिल्म के साथ ही पिछले डेढ़ सालों में लगभग 200 फिल्मों की शूटिंग उत्तराखण्ड में हुई है। पिछली बार जब उनकी मुम्बई में फिल्म जगत से जुड़े लोगों से भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में उन्हें फिल्म शूटिंग के लिये सहयोगात्मक वातावरण प्राप्त हुआ है। इसी का प्रतिफल भी है कि उत्तराखण्ड को बेस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्ही की पहल पर उत्तराखण्ड में सड़क–2 की सूटिंग के लिए फिल्म निर्माता रमेश भट्ट रोमानिया के बजाय उत्तराखण्ड आये। और यहां के सौन्दर्य से अविभूत हुए। उन्होंने इस फैस्टिवल में आये फिल्म कलाकारों एवं फिल्म से जुड़े लोगों से उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के सौन्दर्य से रूबरू होने का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री धन सिंह रावत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि डेरी विकास का उद्देश्य ही किसान व पशुपालकों की बेहतरी है। जो किसान अपने उत्पाद को बाजार तक न ले जा सके उसे उचित मूल्य देकर दुग्ध क्रय करना, उन्हें पशुचारा व पशुओं की उचित देखरेख में आवश्यक मदद करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दुग्ध व्यवसायियों को 21 दिन में भुगतान सुनिश्चत करने, क्षमता विकास, पर्यवेक्षण पर भी ध्यान देने के साथ ही अधिकारियों से किसानों के मध्य जाकर उनकी समस्याओं से अवगत होने तथा उनकी बेहतरी के लिये कार्य करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने दूधातोली व पवाली कांठा क्षेत्र से दुग्ध एकत्र करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस क्षेत्र की दुग्ध उत्पादकता सिमली व श्रीनगर के डेरी फार्म को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास निगम से रू 44462.46 लाख की योजना स्वीकृत कराई गयी है। जिसमें मुख्यतः 5266 सदस्यों को 20000 दुधारू पशु क्रय तथा 52000 दुग्ध उत्पादक सदस्यों को तकनीकी निवेश सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के बच्चों को सुगन्धित मीठा दूध उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना'' स्वीकृत की गयी है, जिसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आ रहे 03 से 06 वर्ष के कुल 1.66 लाख बालक एवं बालिकाओं को सप्ताह में 02 दिन 100 मि.ली. दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इसके इतिरिक्त दुग्ध अत्पादक सदस्यों को पौष्टिक चारा एवं पशुपोषण के लिए मिनिरल मिक्चर तथा प्रोबाइटिक्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना'' स्वीकृत की गयी है। ऑचल दुग्धशालाओं के सृदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा कार्मिकों के कौशल उच्चीकरण हेतु अमूल गुजरात के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.57 लाख दुग्ध उत्पादकों हेतु वर्ष पर्यन्त दूध विक्रय करने के लिए 2619 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है।

प्रदेश में 11 दुग्धशालाऐं गठित है। जिनकी दैनिक प्रसंस्करण क्षमता 2.65 लाख लीटर है। जिनके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 1.68 लाख लीटर गुणवत्ता युक्त तरल दूध तथा अन्य दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में सहकारी समिति अधिनियम अन्तर्गत कुल 2885 दुग्ध समितियों का निबन्धन किया गया है।

बैठक में उच्च शिक्षा एवं दुग्ध विकास राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्धन, सचिव श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी के साथ ही दुग्ध विकास से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने छात्रों के व्यापक हित में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत बतायी है। मुख्यमंत्री ने इसका भी आंकलन करने को कहा है कि इण्टर के बाद कितने छात्र स्नातक में प्रवेश ले रहे हैं। अधिक से अधिक छात्राएं स्नातक में प्रवेश ले सके इसके लिये भी उन्होंने प्रभावी प्रयासों की जरूरत बतायी।

शुक्रवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिये सभी आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जाएं। उन्होंने महाविद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षकों की तैनाती, महाविद्यालयों तक सड़कों की उपलब्धता, भवनों के साथ ही आवासीय व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सभी महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की तैनाती सुनिश्चित की जाय। जिन शिक्षकों की प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति हुई है उन्हें अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करने को कहा जाय। जो शिक्षक जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ पाये जाते हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिये शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाये, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास खण्डों में डिग्री कॉलेज की सुविधा तथा कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत किये जाने के साथ ही कॉलेजों में शिक्षा का बेहतर वातावरण बनाये रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने के. पी.आई के अन्तर्गत कॉलेजों में कैरियर काउंसिलिंग पर भी ध्यान देने तथा कॉलेजों में छात्र, शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाने पर ध्यान देने को कहा।

बैठक में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्धन, सचिव श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी के साथ ही उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 06 सितम्बर, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(09/173)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में सिंचाई एवं पर्यटन विभाग की समीक्षा की। सीएम डेशबोर्ड पर आधारित की–परफोर्मेंस इंडिकेटर पर आधारित समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न प्रोजक्ट के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, हर हाल में निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण कर लिये जाय। अधिकारी प्रत्येक माह कार्य स्थल का भ्रमण कर कार्य की प्रगति देखें। उन्होंने सचिव स्तर से भी फील्ड में कार्यों का निरीक्षण किया जाए। खराब नलकूपों को तुरंत ठीक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी न हो, इसके लिए जरूरत पड़ने पर, अतिरिक्त पम्पों की व्यवस्था भी रखी जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौंग व जमरानी बांध बड़े प्रोजक्ट हैं। सौंग बांध का डिजाइन, फॉरेस्ट क्लीयरेंस व इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस का कार्य जल्द कर लिया जाय। इसके लिए एक सीनियर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाय। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी सभी क्लीयरेंस सम्बन्धी कार्य जल्द कर लिए जाएं। जमरानी बांध के लिए शुरूआती चरण में 47 करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में गगास, पिथौरागढ़ में थरकोट, लोहाघाट के समीप कोलीढ़ेक व पौड़ी में ल्वाली झील के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जनपद हरिद्वार के भौरी में पेयजल के परीक्षण के भी निर्देश दिये हैं, ताकि वहां के निवासियों को हो रही कठिनाई को दूर किया जा सके। वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री ने त्यूनी–प्लासू हाइड्रो प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। बताया गया कि इस वर्ष सितम्बर तक इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेगी।

बैठक में जानकारी दी गई कि केदारपुरी की मंदाकिनी नदी की सुरक्षा का पुनर्निमाण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य नवम्बर 2019 तथा विकासनगर के पांच गांवों में स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई निर्माण की योजना का कार्य, मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। राज्य में फ्लोटिंग सोलर पॉवर संयंत्र की स्थापना के लिए एमओयू हो चुका है। इसकी डीपीआर, निविदा एवं निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। इससे प्रतिवर्ष 3 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद में जो नये थीमबेस्ड डेस्टिनेशन का विकास किया जाना है, इसके लिये सुनियोजित योजना बनाई जाय। नये डेस्टिनेशन के लिए मास्टर प्लान जल्द बनाये जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि समय पर कार्य धरातल पर दिखे। 13 डिस्ट्रिक 13 डेस्टिनेशन के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 06 तकनीकि परामर्शदाता इम्पैनल किये गये हैं। प्रथम चरण में कार्यों का चिन्हीकरण किया गया है। जिलाधिकारियों को 50–50 लाख रूपये की धनराशि निर्गत की गई है। सुरकण्डा देवी रोपवे के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। पूर्णागिरी रोपवे का कार्य प्रगति पर है। केदारनाथ रोपवे के लिए विभाग द्वारा आंतरिक व सिस्मिक सर्वे कराया गया है। नैनीताल व यमुनोत्री रोपवे के लिए भी कार्यवाही गतिमान है। इस वर्ष अभी तक 27 लाख 35 हजार श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं।

बैठक में सिंचाई व पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव डॉ. भूपेन्द्र कौर औलख, श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्रीमती सोनिका, श्रीमती ईवा आशीष श्रीवास्तव व सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग